सं.ए-45011/2/2019-प्रशा.III

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

****

नई दिल्ली, दिनांकः 22 अक्तूबर, 2019

कार्यालय ज्ञापन

मुझे आर्थिक कार्य विभाग से संबंधित सितम्बर, 2019 माह के दौरान महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों के संबंध में मासिक सार के अवर्गीकृत भाग की प्रति परिचालित करने का निदेश हुआ है।

(सुरिन्दर पाल सिंह)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
दूरभाषः 23092100

सेवा में,

1. केन्द्रीय मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. भारत के राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
3. भारत के उपराष्ट्रपति के सचिव, 6, मौलाना आजाद मार्ग, नई दिल्ली।
4. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाऊस, नई दिल्ली।
5. प्रधानमंत्री के निजी सचिव, प्रधानमंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली।
6. मत्रिमंडल सचिव के निजी सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
7. उपाध्यक्ष, नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
8. सभी सदस्य, नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
9. सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव, भारत सरकार, नई दिल्ली।
   सचिव (आर्थिक कार्य) के प्रधान निजी सचिव, सचिव (राजस्व) के प्रधान निजी सचिव, सचिव (व्यय) के प्रधान निजी सचिव, वित्त राज्य मंत्री के विशेष कार्याधिकारी।
10. मुख्य आर्थिक सलाहकार, आर्थिक कार्य विभाग।
11. अपर सचिव (श्री ए. गिरिधर), मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
12. डा. सी.एस. महापात्रा, अपर सचिव, आर्थिक कार्य विभाग।
13. श्री के. राजारामन, अपर सचिव (प्रशासन एंड सीएस), आर्थिक कार्य विभाग
14. श्री समीर कुमार खरे, अपर सचिव (एफबी एंड एडीबी), आर्थिक कार्य विभाग।
15. सुश्री मीरा स्वरूप, अपर सचिव और वित्त सलाहकार (वित्त)।
16. श्री संजीव सान्याल, प्रधान आर्थिक सलाहकार, आर्थिक कार्य विभाग।
17. आर्थिक कार्य विभाग के सभी प्रभागाध्यक्ष।
    संयुक्त सचिव (बजट)/संयुक्त सचिव (सीएंडसी/यूएनएंडओएमआई)/संयुक्त सचिव (आईपीएफ)/संयुक्त सचिव (एफएम)/संयुक्त सचिव (बीसी एंड आईईआर)/सलाहकार (आईईआर)/सीएए।
18. सुश्री राजश्री रे, सलाहकार, आर्थिक कार्य विभाग।
19. डा. शशांक सक्सेना, सलाहकार (एफएसआरएल), आर्थिक कार्य विभाग।
20. श्री अरूण कुमार, सलाहकार, आर्थिक कार्य विभाग।
21. श्री राजेश मल्होत्रा, अपर महानिदेशक (एम एंड सी), वित्त मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
22. गार्ड फाइल - 2019

सं. ए-45011/2/2019-प्रशा.III

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

विषय: सितम्बर, 2019 माह के दौरान आर्थिक कार्य विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों के संबंध में मासिक सार।

1. वृहत आर्थिक सिंहावलोकन

1.1 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (नई श्रृंखला-संयुक्त) पर आधारित हैडलाइन मुद्रास्फीति अगस्त, 2018 में 3.69 प्रतिशत की तुलना में अगस्त, 2019 में 3.21 प्रतिशत थी। थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) पर आधारित मुद्रास्फीति अगस्त, 2018 में 4.62 प्रतिशत की तुलना में अगस्त, 2019 में 1.08 प्रतिशत रही। जुलाई 2019 में औद्योगिक श्रमिकों सीपीआई-आईडब्ल्यू हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के रूप में मुद्रास्फीति जुलाई, 2018 में 5.61 प्रतिशत की तुलना में 5.98 प्रतिशत थी। अगस्त, 2019 में कृषि श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और ग्रामीण श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्रमश: 6.39 प्रतिशत और 6.23 प्रतिशत रही।

1.2 बैंक ऋण में वृद्धि अगस्त, 2019 के अंत में पिछले वर्ष की इसी अवधि के अंत में 13.4% की तुलना में 10.2% प्रतिशत रही। 10 वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों पर प्रतिफल 16 अगस्त, 2019 के 6.69 प्रतिशत की तुलना में 13 सितम्बर, 2019 को 6.77 प्रतिशत रहा।

1.3 भारत का विदेशी मुद्रा भंडार मार्च अंत, 2019 के 411.9 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर से 17.7 बिलियन अमरीकी डालर की बढ़त दर्शाते हुए 6 सितम्बर, 2019 की स्थिति के अनुसार 429.6 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। अगस्त, 2019 में 71.14 रुपए प्रति अमरीकी डालर की तुलना में रुपए की औसत मासिक विनिमय दर (संदर्भ दर) सितम्बर, 2019 माह में 71.55 रुपए प्रति अमरीकी डालर रही।

1.4 केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (वर्ष 2011-12 की नई श्रृंखला पर आधारित) द्वारा जारी त्वरित अनुमानों के अनुसार, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में जुलाई, 2018 में 6.5 प्रतिशत की बढ़त की तुलना में जुलाई, 2019 में 4.3 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई। अप्रैल-जुलाई, 2019-20 की अवधि हेतु औद्योगिक बढ़त अप्रैल-जुलाई, 2018-19 के दौरान हुई 5.4 प्रतिशत की बढ़त की तुलना में 3.3 प्रतिशत थी।

1.5 भारत का व्यापारिक माल निर्यात अगस्त, 2018 के दौरान 27.8 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 6.0 प्रतिशत की गिरावट दर्शाते हुए अगस्त, 2019 के दौरान 26.1 बिलियन अमरीकी डालर रहा। भारत का आयात अगस्त, 2018 में 45.7 बिलियन अमरीकी डालर के आयात मूल्य के स्तर की तुलना में 13.4 प्रतिशत घटकर अगस्त 2019 के दौरान 39.6 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। भारत का तेल आयात अगस्त, 2019 के दौरान 10.9 बिलियन अमरीकी डालर रहा जो कि अगस्त 2018 में 11.9 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 8.9 प्रतिशत कम था।

1.6 व्यापार घाटा अगस्त, 2018 के दौरान 17.9 बिलियन अमरीकी डालर के घाटे की तुलना में अगस्त, 2019 में 13.4 बिलियन अमरीकी डालर अनुमानित था।

1.7 जुलाई, 2019 के दौरान सेवाओं का निर्यात और आयात क्रमश: 19.1 बिलियन अमरीकी डालर और 12.8 बिलियन अमरीकी डालर रहा। जुलाई, 2019 के लिए सेवाओं में व्यापार शेष 6.3 बिलियन अमरीकी डालर अनुमानित था।

2. अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम

2.1 (क) माननीय वित्त मंत्री ने 14 सितम्बर, 2019 को घोषणा की कि ईसीबी दिशानिर्देशों में घर खरीददारों, जो आरबीआई के संबंध में पीएमएवाई के अंतर्गत पात्र हैं, को वित्तपोषण की सुविधा प्रदान करने हेतु छूट दी जाएगी।

(ख) वित्तीय सेवाएं विभाग के प्रस्ताव पर दिनांक 19.09.2019, 26.09.2019 और 27.09.2019 के द्वारा क्रमशः आईडीबीआई बैंक लि., आठ पीएसयू और पांच पीएसबी में पूंजी लगाने हेतु भारत राजपत्र में विशेष प्रतिभूति बांड जारी किए गए।

(ग) (i) माननीय वित्त मंत्री के अनुमोदन से सचिव (आर्थिक कार्य) की अध्यक्षता में सदस्यों के रूप में वित्तीय वर्ष 2019-20 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक प्रत्येक वर्ष के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना की रूपरेखा बनाने हेतु सीईओ, नीति आयोग, सचिव, व्यय, प्रशासनिक मंत्रालयों के सचिव, अपर सचिव (निवेश), आर्थिक कार्य विभाग और सदस्य सचिव के रूप में संयुक्त सचिव, अवसंरचना नीति और वित्तीय प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग को सम्मिलित करने हेतु एक कार्य बल का गठन किया गया। कार्य बल की प्रथम बैठक 09.09.2019 और 25.09.2019 को चौथी बैठक हुई। अब तक चार मंत्रालयों/विभागों जैसे कि एमओएचयूए, डीओएसी एंड एफडब्ल्यू, डीईपीडी और एमओपीएनजी ने प्रक्रियाधीन अवसंरचना को अंतिम रूप देने हेतु विचार विमर्श किया।

(ii) पीपीपीएसी ने निम्नलिखित परियोजनाओं के सैद्धांतिक रूप को अनुमोदित किया।

(क) पीपीपी मोड के तहत लालजी बे, लांग आइलैंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पारिस्थितिकी पर्यटन स्तल (इको टूरिज्म रिसोर्ट) का विकास।

(ख) पीपीपी मोड के अंतर्गत मिनीकॉय आइलैंड, लक्षदीप आईलैंड में पारिस्थितिकी पर्यटन स्थल का विकास।

2.2 इस माह के दौरान निम्नलिखित ऋण श्रृंखलाएं दी गईं:

i. मंगोलिया में पेट्रोरसायन शोधशाला परियोजना हेतु 1 बिलियन अमरीकी डॉलर की ऋण श्रृंखला को पूरा करने हेतु मंगोलिया सरकार को 236.00 मिलियन अमरीकी डॉलर की राशि की अतिरिक्त ऋण श्रृंखला प्रदान की गई;

ii. विदेश नीति प्रशिक्षण संस्थान केंद्र निर्माण को पूरा करने हेतु घाना सरकार को 2.01 मिलियन अमरीकी डालर की अतिरिक्त ऋण श्रृंखला दी गई;

iii. गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जीएसएल) से ट्रेनिंग शिप के अर्जन हेतु नाइजीरिया सरकार को 50.48 मिलियन अमरीकी डालर की अतिरिक्त ऋण श्रृंखला दी गई; और

iv. गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जीएसएल) से लैंडिंग शिपटैंक (एलएसटी) की खरीद के लिए नाइजीरिया सरकार को 70.00 मिलियन अमरीकी डालर की अतिरिक्त ऋण श्रृंखला दी गई।

2.3 अगस्त, 2019 तक के व्यय की 2019-20 के लिए बजटीय अनुमान से तुलना

अगस्त, 2019 माह के लिए मासिक लेखे की बिना लेखा परीक्षा अनंतिम विवरण के अनुसार 31 अगस्त, 2019 की स्थिति के अनुसार राजकोषीय घाटा 5,53,840 करोड़ रुपए था, जो 2019-20 के लिए बजट अनुमान (7,03,760 करोड़ रुपए) का 78.7 प्रतिशत है। अगस्त, 2018 के अंत में राजकोषीय घाटा पिछले वर्ष की उसी अवधि (सीओपीपीवाई) में बजट अनुमान का 94.7 प्रतिशत था। वित्तीय वर्ष के दौरान मासिक विवरण में दर्शाए गए राजकोषीय घाटे के आंकड़े उस वर्ष के राजकोषीय घाटे के आवश्यक रूप से सूचक नहीं होते क्योंकि यह विभिन्न संक्रमणकालीन कारकों, प्राप्तियों और व्यय दोनों के कारण उस माह तक की गैर ऋण प्राप्तियों और व्यय के प्रवाह में अस्थाई असंतुलन द्वारा प्रभावित होता है, जिसे वस्तुतः वित्तीय वर्ष के अंत में समायोजित कर लिया जाता है।

प्राप्तियों के क्षेत्र में, अगस्त, 2019 तक कुल गैर-ऋण प्राप्तियां 6,21,461 करोड़ रुपए थीं जो बजट अनुमान (सीओपीपीवाई में 26.4 प्रतिशत) का 29.8 प्रतिशत है। कुल राजस्व प्राप्तियां 2019-20 में बजट अनुमान का 30.7 प्रतिशत थीं जो पिछले वर्ष की उसी अवधि में 26.9 प्रतिशत थीं। अगस्त, 2019 के अंत में सकल कर राजस्व (जीटीआर) बजट अनुमान (सीओपीपीवाई-बजट अनुमान का 27.9

प्रतिशत) का 26.8 प्रतिशत था। कर राजस्व (निवल) बजट अनुमान (सीओपीपीवाई में 24.7 प्रतिशत) का 24.5 प्रतिशत था जबकि गैर-कर राजस्व प्राप्तियां बजट अनुमान (सीओपीपीवाई में 40.1 प्रतिशत) का 63.4 प्रतिशत थी। गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां बजट अनुमान (सीओपीपीवाई में 16.3 प्रतिशत) का 15.2 प्रतिशत थी। व्यय के क्षेत्र में, अगस्त, 2019 के अंत में कुल व्यय 11,75,301 करोड़ रुपए था जो बजट अनुमान (सीओपीपीवाई में 43.8 प्रतिशत) का 42.2 प्रतिशत है। इसमें बजट अनुमान (सीओपीपीवाई का 43.8 प्रतिशत) का 42.4 प्रतिशत का राजस्व व्यय और बजट अनुमान (सीओपीपीवाई में 44.1 प्रतिशत) का 40.3 प्रतिशत का पूंजीगत व्यय शामिल है। ब्याज अदायगी सीओपीपीवाई में 38.1 प्रतिशत की तुलना में 33.2 प्रतिशत थी।

2.4 सितम्बर, 2019 माह के दौरान निम्नलिखित बैठकें आयोजित की गईं:-

i. नई दिल्ली में दिनांक 25.9.2019 को हुई 9वीं भारत-चीन वित्तीय वार्ता में सचिव (आर्थिक कार्य) ने भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया। दोनों पक्षों ने वृहत आर्थिक परिस्थितियों और नीति, बहुपक्षीय संरचना में सहयोग, द्विपक्षीय निवेश तथा वित्तीय सहयोग पर गहन विचार विमर्श किया। वित्तीय वार्ता के अंत में आपसी सहमति दर्शाते हुए एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया तथा वित्तीय क्षेत्र में सहयोग को अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए दोनों देशों ने अपनी दूरदर्शिता सांझा की।

ii. गवर्नर, आरबीआई की अध्यक्षता में हुई वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद-उप समिति (एफएसडीसी-एससी) की 23वीं बैठक में सचिव (आर्थिक कार्य) ने मुख्य आर्थिक सलाहकार के साथ भाग लिया। उप-समिति में अध्यक्ष, सेबी, अध्यक्ष आईआरडीएआई, अध्यक्ष आईबीबीआई, आरबीआई के डिप्टी-गवर्नर, सचिव, एफएसडीसी, डॉ. दीपक मोहंती, ईडी, आरबीआई और पूर्णकालिक सदस्य, पीएफआरडीए ने भी भाग लिया।

iii. अर्ली वार्निंग ग्रुप, जो कि एफएसडीसी-एसपी के अंतर्गत एक तकनीकी ग्रुप है, की 14वीं बैठक 13 सितम्बर, 2019 को हुई। इस बैठक में प्रमुख विषयों पर चर्चा की गई जिसमें जोखिम दृष्टिकोण रखने वाले प्रमुख वृहत आर्थिक विकास, मौजूदा वैश्विक आर्थिक मंद-भारत के वित्तीय बाजारों का विस्तार, एनबीएफसी/एचएफसी क्षेत्रों आदि का विकास शामिल है।

iv. अपर सचिव (एफबी और एडीबी) की अध्यक्षता में आर्थिक कार्य विभाग की जांच समिति की 99वीं बैठक 17 सितम्बर, 2019 को हुई।

v. भारत में स्थानीय बंधपत्र बाजार (लोकल बांड मार्केट) के विकास के संबंध में चर्चा करने हेतु एमडीबी/आरबीआई/एसईबीआई/एफएम के साथ अवर सचिव (एफबी और एडीबी) की अध्यक्षता में 16 सितम्बर, 2019 को एक बैठक आयोजित की गई।

vi. अपर सचिव (एफबी और एडीबी) की अध्यक्षता में 18 सितम्बर, 2019 को आर्थिक कार्य विभाग में अक्तूबर, 2019 के दौरान अध्यक्ष, विश्व बैंक ग्रुप (डब्ल्यूबीजी) के भारत दौरे के संबंध में एक बैठक हुई। बैठक में विश्व बैंक, एमईए, डीओपीटी, डीपीआईआईटी (ईओडीबी), एमएचआरडी, नीति आयोग, डीएफएस, बीसी प्रभाग, सिडबी और एक्सिम बैंक के प्रतिनिधि उपस्थित हुए।

vii. अपर सचिव (एफबी और एडीबी) की अध्यक्षता में 19 सितम्बर, 2019 को श्री एंजो डी लॉरेंटीस, मुख्य क्रय अधिकारी, विश्व बैंक और विश्व बैंक के अन्य अधिकारियों के साथ विश्व बैंक की क्रय नीति पर बातचीत करने हेतु एक बैठक का आयोजन किया गया।

viii. अपर सचिव (एफबी और एडीबी) की अध्यक्षता में 13 सितम्बर, 2019 को विश्व बैंक देश भागीदारी रूपरेखा (वित्तीय वर्ष 18-22) के अंतर्गत राज्यों की भागीदारी के संचालन पर बैठक का आयोजन किया गया। विश्व बैंक का प्रतिनिधित्व सुश्री भावना भाटिया, प्रोग्राम लीडर, ईएफआई ने किया।

ix. आर्थिक कार्य विभाग ने 20-27 सितम्बर, 2019 को वियतनाम में हुई क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) टीएनसी के 28वें दौर तथा संबंधित बैठक में भाग लिया।

x. 17 सितम्बर, 2019 को भारत और यूएई के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि (बीआईटी) पर वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से चर्चा हुई।

xi. 12 सितम्बर, 2019 को भारत और सऊदी अरब के बीच की बीआईटी पर वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से चर्चा हुई।

xii. दिनांक 26.09.2019 को अनआईआईएफ ट्रस्टी लिमिटेड की बोर्ड बैठक हुई।

xiii. दिनांक 27.09.2019 को एनआईआईएफ ट्रस्टी लिमिटेड की वार्षिक आम बैठक हुई।

3. न्यूनतम सरकार, अधिकतम अभिशासन

विशेषकर, सूचना के प्रस्तुतीकरण में आईसीटी के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है।

4. एसीसी के निदेशों/आदेशों का पालन न किया जाना

शून्य।

5. माह के दौरान स्वीकृत किए गए एफडीआई प्रस्ताव और विभाग में अनुमोदन हेतु लंबित एफडीआई प्रस्तावों की स्थिति

स्वीकृत किए गए	:	00
विभाग में अनुमोदन हेतु लंबित	:	08

****